भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1495

उत्तर देने की तारीख 05.12.2011

बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

1495. श्री मोइनुल हसन :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **सरकार के बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम** (एमएसडीपी) **की स्थिति का ब्यौरा क्या है**;

(ख) **सरकार द्वारा इस कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों का सीमांकन करने के लिए किन स्रोतों का इस्तेमाल किया गया**;

(ग) **क्या सरकार इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ रहे क्षेत्रों में वृद्धि करने की योजना बना रही है**; **और**

(घ) **यदि हां**, **तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है** ?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (**श्री विन्सेंट एच. पाला**)

(**क**) : 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 20 राज्यों/संघ राज्यों के अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के कार्यान्वयन के लिए आवंटित कुल राशि 3780 करोड़ रु0 है। इस कार्यक्रम के तहत 3340.19 करोड़ रु0 राशि की जिला योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। राज्यों/संघ राज्यों द्वारा मंत्रालय में प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के आधार पर उन्हें 2359.39 करोड़ रु0 राशि की केन्द्रीय वित्तीय सहायता निर्गत की जा चुकी है।

(**ख**) : सरकार ने वर्ष 2001 की जनगणना के आकड़ों के अनुसार चुनिन्दा सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और आधारभूत सुविधा मानदंडों की दृष्टि से परस्पर पिछड़ेपन और

अल्पसंख्यक आबादी को आधार मानते हुए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों की पहचान की है।

(**ग**) : जी, नहीं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक बहुल जिलों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(**घ**) : उपर्युक्त (ग) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

*****